

यूपी में कम बारिश का अलर्ट CM योगी का एक्शन, जारी हुआ नया आदेश

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> 1. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक्शन में सीएम योगी, कैच द रेन को बनाया जनआंदोलन...
 - >> जनभागीदारी से बदलेगी तस्वीर...
- >> 2. यूपी में सामान्य से कम बारिश का अलर्ट मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान...
 - >> पूरबी और पश्चिमी यूपी दोनों पर असर...
- >> 3. पेयजल संकट से निपटने की पुख्ता तैयारी अधिकारियों को निर्बाध जलापूर्ता के सख...
 - >> शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कड़े नियम...
- >> 4. समेकित कार्ययोजना पर जोर तालाबों और अमृत सरोवरों को गंदे पानी से बचाने की पह...
 - >> अमृत सरोवरों का नियमित रखरखाव...
- >> 5. जल संरक्षण का आदर्श मॉडल बनेंगे सरकारी भवन मशिन मोड में वर्षाजल संचयन...
 - >> नियमों का कड़ाई से पालन...
- >> 6. भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार अतदिहति विकासखंडों की संख्या में आई भारी कमी...
 - >> आंकड़ों की जुबानी यूपी का जल सुधार...
- >> 7. अटल भूजल और अन्य अहम परियोजनाओं के सकारात्मक परिणाम यूपी ने हासिल किया जल सं...
 - >> अत्याधुनिक योजनाओं का क्रियान्वयन...
 - >> नष्टिकर्ष...
 - >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

उत्तर प्रदेश में मानसून की अनिश्चितता और मौसम विभाग की हालिया चेतावनी के बाद राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संकट की संभावनाओं को देखते हुए एक उच्चस्तरीय बैठक की और राज्य में जल संरक्षण को लेकर बड़े निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पानी की बचत और संचयन को अब एक सरकारी कार्यक्रम के बजाय व्यापक जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिवाई, पंचायती राज, भूगर्भ जल विभाग, नमामि गंगे और कृषि विभाग सहित कई प्रमुख विभागों के अधिकारी शामिल हुए। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी महीनों में आम जनता को पेयजल और सचिवाई के पानी की कमी का सामना न करना पड़े। इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे विशेष अभियानों की स्थिति और प्रगतिकी भी समीक्षा की गई है।

1. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक्शन में सीएम योगी, कैच द

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को जल संचयन के

कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया। मौसम की अनश्चितता को देखते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संरक्षण के इस राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ना होगा। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी की एक-एक बूंद को सहेजा जा सके।

जनभागीदारी से बदलेगी तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए कैच द रेन (Catch the Rain) अभियान को उत्तर प्रदेश में अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि जल संरक्षण के प्रयास केवल फाइलों या वित्तीय बजट तक सीमित नहीं रहने चाहिए। जब तक इसमें आम नागरिकों, युवाओं और सामाजिक संगठनों की व्यापक जनभागीदारी नहीं होगी, तब तक इसके स्थायी परिणाम नहीं मिल सकते।

>> अभियान का उद्देश्य: वर्षा के जल को जहां भी और जैसे भी संभव हो, संचित करना।

>> मुख्य रणनीति: ग्रामीण इलाकों में चौपालों के माध्यम से लोगों को वर्षाजल संचयन (Rainwater Harvesting) के लिए प्रेरित करना।

>> नवीनतम अपडेट (Latest Update): सरकार जल्द ही इसके लिए एक विस्तृत गाइडलाइन और जिलों की प्रगति सूची (List) जारी करेगी।

2. यूपी में सामान्य से कम बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग का ताजा

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी दीर्घावधि पूर्वानुमान के अनुसार, वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस चेतावनी ने सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिसके कारण अग्रिम रणनीतियों पर काम शुरू हो चुका है। मौसम विशेषज्ञों ने बैठक में बताया कि जून से लेकर सितंबर तक के चार महीनों में मानसून की रफ्तार धीमी रह सकती है।

पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों पर असर

मौसम विभाग के अनुसार, इस बार मानसून की अनियमितता का प्रभाव किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दोनों ही हिस्सों में सामान्य के मुकाबले कम बारिश होने के संकेत मिले हैं। इसके अलावा, शुरुआती महीनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है, जिससे जल स्रोतों के तेजी से सूखने का खतरा मंडरा रहा है।

इस मौसमी बदलाव और कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए कृषि और संचाई विभाग को विशेष एडवाइजरी जारी करने को कहा

गया है। किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कठिने पानी के विकल्पपूर्ण उपयोग के साथ-साथ कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्राथमिकता दें। राज्य सरकार इस संबंध में एक वसितुत कार्यक्रमोजना का PDF भी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराएगी, जैसे किसान ऑनलाइन चेक (Check) कर सकेंगे।

3. पेयजल संकट से निपटने की पुख्ता तैयारी: अधिकारियों को नरि

संभावित सूखे और कम बारिश की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े लहजे में नरिदेश दिया है कि राज्य के किसी भी हस्से में पेयजल संकट की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की उपलब्धता नागरिकों का बुनियादी अधिकार है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की जलापूर्ति व्यवस्था की दैनिक निगरानी करने को कहा गया है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कड़े नियम

जलापूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारु और नरिबाध बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे को दुसुत किया जा रहा है। गर्मियों और मानसून के महीनों में पाइपलाइन नेटवर्क और हैडपंपों के संचालन पर विशेष नजर रखी जाएगी। इस संदर्भ में सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाने के नरिदेश दिए हैं:

>> कंट्रोल रूम की स्थापना: पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए हर जिले में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा।

>> अवैध कनेक्शनों पर रोक: मुख्य पाइपलाइनों से होने वाली पानी की चोरी और बर्बादी को रोकने के लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा।

>> टैंकों की व्यवस्था: जल क्षेत्रों में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, वहां अग्रिम रूप से पानी के टैंकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

इस तरह के जल संकट प्रबंधन को समझने के लिए आप देश के अन्य हस्सों में चल रहे अभियानों की स्थिति भी देख सकते हैं, जैसे कबूँदी में जल जीवन मशिन का रोकें: हर घर पीयूष जल अब होगा नयिकुत! के तहत कए जा रहे प्रयास।

4. समेकित कार्यक्रमोजना पर जोर: तालाबों और अमृत सरोवरों को गंटे

जल संरक्षण के कार्यों को गति देने के लिए सीएम योगी ने किसी एक विभाग पर नरिभर रहने के बजाय एक समेकित कार्यक्रमोजना (Integrated Action Plan) तैयार करने का आदेश दिया है। इस योजना के तहत सचिाई, पंचायती राज, भूगर्भ जल विभाग, नमामागिंगे, राजस्व और कृषि विभाग मलिकर काम करेंगे। विभागों के आपसी समन्वय से जल संचयन के बुनियादी ढांचे को मजबूत

किया जाएगा।

अमृत सरोवरों का नियमति रखरखाव

ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत को बनाए रखने के लिए नरिमति कएि गए अमृत सरोवरों की सुरक्षा और स्वच्छता सरकार की सर्वोच्च प्राथमकितओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज वभाग को वशिष रूप से नरिदेशति कयिा है कगिांवां का गंदा पानी या नालयिों का वेस्ट वाटर कसिी भी परसिथति में इन शुद्ध तालाबों और पोखरों में नही मलिना चाहएि। इसके लएि वलिज लेवल पर वाटर ट्रीटमेंट और सोक पटि (Soak Pit) जैसी व्यवस्थाएं वकिसति की जाएंगी।

अमृत सरोवरों के नियमति रखरखाव और उनकी स्वच्छता को लेकर स्थानीय ग्राम पंचायतों की जवाबदेही तय की जा रही है। इन सरोवरों के चारों ओर वृक्षारोपण करने का भी नरिदेश दयिा गया है ताकजिल का वाष्पीकरण कम हो और पर्यावरण भी सुरक्षति रहे। ग्रामीण युवा इस योजना के तहत रोजगार के अवसरों के लएि भीवर्षा यादव: नवभारत टाइम्स की वो तेज-तरार पत्रकार जो दलिाएंगी आपको सरकारी नौकरी!जैसे करयिर अपडेट्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं से जुड़ी नयिक्तयिों की जानकारी ले सकते हैं।

5. जल संरक्षण का आदर्श मॉडल बनेगे सरकारी भवन: मशिन मोड में

जनता को जल संरक्षण के प्रति प्रेरति करने के लएि सरकार खुद एक मसिल पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने नरिदेश दयिा है कउत्तर प्रदेश के सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों, स्कूलों और परषिदीय वदियालयों को जल संरक्षण के आदर्श मॉडल (Ideal Model) के रूप में वकिसति कयिा जाएगा। इन सभी इमारतों में मशिन मोड पर काम करते हुए रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टगि ससि्टम (Rooftop Rainwater Harvesting System) अनवार्य रूप से स्थापति कयिा जाएगा।

नयिमों का कड़ाई से पालन

सरकारी भवनों के अलावा नए बनने वाले नजिी आवासीय और व्यावसायकि परसिरो के लएि भी जल संचयन प्रणालयिों को अनवार्य कयिा जा रहा है। वकिस प्राधकिरणों को नरिदेश दयिा गया है कवे बनिा रेनवाटर हार्वेस्टगि के नक्षा पास न करें। इसके अतरिकित, युवाओं और छात्रों को इस अभयिान से जोड़ने के लएि शैक्षणकि संस्थानों में भी जल साक्षरता से जुड़े कार्यक्रम आयोजति कएि जाएंगे। राज्य के छात्र जो हाल ही में अपनी परीक्षाओं से मुक्त हुए हैं औरयूपी बोर्ड रजिल्ट 2026के बाद आगे की पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी इन सामाजकि और पर्यावरण अभयिानों का हसिसा बनाया जाएगा।

6. भूजल स्रोत में उल्लेखनीय सुधार: अतदिोहति वकिसखंडों की संख

उच्चस्तरीय बैठक के दौरान भूगर्भ जल विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य में भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) को लेकर एक उत्साहजनक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पछिले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा कए गए नरितर परयासों के कारण उत्तर प्रदेश के भूजल स्तर में काफी सकारात्मक सुधार देखने को मलल है। आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट कयल गयल कलरलज्य की जल नीतयलं सही दशल में काम कर रही हैं।

आंकड़ों की जुबानी यूपी का जल सुधार

समीक्षा बैठक में रखे गए आधकलरकल आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने भूजल दोहन को नयलंतरतल करने में बड़ी सफलता हासलल की है:

>> अतदोहलतल ब्लॉकों की संख्या:वर्ष 2013 में राज्य के भीतर अतदोहलतल (Over-exploited) वकलसखंडों की संख्या 113 थी, जो वर्ष 2025 तक घटकर केवल 44 रह गई है।

>> भूजल पुनर्भरण में वृद्धल:वर्ष 2017 में वभलनलन स्रोतों के माध्यम से लगभग 30.59 लाख करोड़ लीटर भूजल का पुनर्भरण होता थल, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 35.79 लाख करोड़ लीटर हो गयल है।

>> कुल वार्षकल पुनर्भरण:इसी अवधल के दौरान प्रदेश का कुल वार्षकल भूजल पुनर्भरण 69.91 लाख करोड़ लीटर से बढ़कर 73.39 लाख करोड़ लीटर के स्तर को पार कर गयल है।

इसके साथ ही, सतत वकलस लक्ष्य-6 (SDG-6) के तहत नरलधलरतल मानकों को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश ने भूजल दोहन की दर को 70 प्रतिशत के नयलंतरतल स्तर पर लाने का ऐतहलसकल लक्ष्य प्राप्त कर लयल है। पछिले वर्षों की तुलनात्मक दर इस प्रकार रही है:

7. अटल भूजल और अन्य अहम परयलोजनाओं के सकारात्मक परणलम: यूपी

उत्तर प्रदेश के 29 जनपदों में पछिले कुछ वर्षों के दौरान औसत भूजल स्तर में भारी सुधार देखा गयल है। पछिले 10 वर्षों के आंकड़ों का वशल्लेषण करने पर पतल चलतल है कलरलज्य के 361 वकलसखंडों के वलटर टेबल में बढ़ोतरी हुई है। इनमें से 172 वकलसखंड ऐसे हैं जहां प्रतिवर्ष 10 सेंटीमीटर से अधकल और 69 वकलसखंडों में पछिले एक दशलक में 20 सेंटीमीटर से अधकल का सुधार दर्ज कयल गयल है।

अत्याधुनकल यलोजनाओं का करयलान्वयन

भूगर्भ जल विभाग द्वारा राज्य में कई नवीन और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जल परयलोजनाओं का संचालन कयल जल रहा है। इन यलोजनाओं के सफल करयलान्वयन के कारण ही आज उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरल है। मुख्य

रूप से संचालित कार्यक्रमों की सूची निम्नलिखित है:

>> उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना: इसके तहत सामुदायिक स्तर पर जल बजटिंग और संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

>> इण्डो-इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना: बुंदेलखंड जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इजरायली उन्नत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

>> वर्षाजल संचयन थीम पार्क और भूजल सप्ताह: जनमानस को जागरूक करने के लिए समय-समय पर प्रदर्शनों और सूचनात्मक अभियानों का आयोजन।

>> डिजिटल नगरानी: राज्यव्यापी भूजल नगरानी नेटवर्क के माध्यम से वास्तविक समय (Real-time) में जल स्तर के उतार-चढ़ाव को ट्रैक किया जा रहा है।

इसके साथ ही, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने बताया कि मानसून के आगमन से पहले राज्य की प्रमुख नदियों की सल्ट सफाई (Desilting) का कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि नदियों की जल संग्रहण क्षमता बढ़े और बाढ़ जैसी स्थितियों पर भी नियंत्रण पाया जा सके।

नष्टिर्ष

मौसम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश की चेतावनी नष्टिर्ष रूप से एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार की समयबद्ध और समेकित रणनीतियों ने इस चुनौती से निपटने का मजबूत भरोसा दिया है। कैच द रेन अभियान को जनआंदोलन बनाकर और सरकारी स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करके यूपी जल संकट से सुरक्षा दूरी बनाने की राह पर अग्रसर है। आंकड़ों में देखि रहा भूजल स्तर का सुधार इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो प्राकृतिक वसिंतियों के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब यह प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है कि वे पानी की बर्बादी को रोकें और जल संचयन को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

मौसम विभाग के दीर्घावधि पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश में जून से सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

कैच द रेन वर्षा के जल को संचित करने का एक विशेष अभियान है। मुख्यमंत्री ने इसे एक व्यापक जनआंदोलन बनाने और सभी सरकारी भवनों में रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं।

यूपी में भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य में अतदीहिती विकासखंडों की संख्या वर्ष 2013 में 113 थी, जो घटकर अब केवल 44 रह गई है और कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण बढ़कर 73.39 लाख करोड़ लीटर पहुंच गया है।

MSNTARGET.COM

<https://msntarget.com>

उत्तर प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्य-6 के अंतर्गत भूजल दोहन की दर को नियंत्रित करते हुए 70 प्रतिशत के स्तर पर लाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।

पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया गया है कि गांवों का गंदा पानी स्थानीय तालाबों और अमृत सरोवरों में न जाने पाए। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर पानी के स्वच्छता और नियमित रखरखाव की व्यवस्था किसति की जा रही है।